VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1510)

Name of Candidate	रोशन मीणा		
Medium Eng./Hindi	हिंदी	Registration Number	4144
Center	ऑन लाइन	Date	15/12/21

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका मे सूचनाए भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमाक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमे बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम मे लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका मे खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. Highlight the role played by the MPLAD Scheme in creating community assets based on local needs. Also, critically evaluate the recent move to suspend it. **(150 words) 10**

स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में MPLAD योजना द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इसे निलंबित करने के हालिया कदम का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

'MPLAD' योजना 1992 से प्रारंभ की गई थी इसमे संसद सदस्यों को प्रतिवर्ष विकास कार्यों में खर्च के वित्तीय अधिकार दिये जाते है जिन्हे जिला अधिकारी की स्वीकृति से सड़क, जनजातीय कल्याण, पर्यावरण के जैसे क्षेत्रों में खर्च किया जाता है।

MPLAD योजना की भूमिका

① आपदा प्रबंधन में राहत सहायता के रूप मे खर्च करना

② जनजातियों जातियों के कल्याण

③ सांसद गाँव गोद लेने में खर्च

④ विकासात्मक पूरक सहायता - सड़क, पेयजल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑤ सांसद जन कल्याण का उपकरण
⑥ जवाबदेही को सुनिश्चित करने में

हाल ही में निलंबन का कारण -
① कोविड - 19 जनित महामारी की स्थिति
② स्वास्थ्य पर अधिक व्यय पर बल
③ राष्ट्रीय राजस्व प्रबंधन हेतु दक्षतापूर्ण खर्च सुनिश्चित करने हेतु

समस्या
① कोविड - 19 प्रबंधन में सांसदों के महत्व जरूरतों की उपेक्षा की गई।
② स्थानीय कोविड स्तर मुद्दों की उपेक्षा जैसे - टीकाकरण

हाल ही में पुनः योजना को शुरू किया गया है जो सही कदम है। योजना को दक्षता, लागत - लाभ के आधार पर जारी रखा जाना चाहिए।

2. Adequately empowering the third tier of Indian federal structure is key to strengthen federalism in India. Analyse. (150 words) 10

भारतीय संघीय ढांचे के तृतीय स्तर को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाना, भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने की कुंजी है। विश्लेषण कीजिए।

संघीय ढाँचा भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची तथा 73/74वें संविधान संशोधन से मजबूत हुआ है।

भारतीय संघीय ढांचे में तृतीय स्तर पंचायतों और नगरपालिका को संदर्भित है।

संघीय प्रशासन पदसोपान

भारतीय संघवाद में तृतीय ढांचे की भूमिका

① नीचे से विकास सुनिश्चित करने में सहायक – नीति आयोग ने @75 रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की।

② भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रशासन की दक्षता एवं जवाबदेही

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महत्वपूर्ण है।

(3) लोकतंत्र में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने में - 73वें 74वें संविधान संशोधन में 33% महिला आरक्षण एवं अस्पृश्यता मुक्ति में सहायता की।

(4) स्थानीय वित्तीय प्रबंधन में सहायक - 15वें वित्त आयोग ने स्वीकारा

(5) स्थानीय समस्या स्थानीय समाधान की रणनीति प्रभावशाली है।

(6) कोविड - 19 प्रबंधन (महामारी नियंत्रण) स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की उपलब्धता में सहायक)

(7) केंद्रीय सरकार के कार्यभार को कम करने में सहायक होता है।

(8) संविधान की भावना अनुरूप है।

इस प्रकार तृतीय स्तर पर पर्याप्त सशक्त बनाना तकनीक, वित्त, अधिकार, स्वायत्तता जवाबदेही के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. To safeguard and uphold the freedom of speech and expression in India, it is imperative to adequately reform colonial laws that curtail free speech. Discuss. **(150 words) 10**

भारत में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और उसे बनाए रखने के लिए, मुक्त वाक् को कम करने वाले औपनिवेशिक कानूनों में पर्याप्त रूप से सुधार करना अनिवार्य है। चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता तथा अनु० 21 में 'जीवन के अधिकार' में भी प्रावधान किया गया है।

वाक् अभिव्यक्ति का महत्व

1. निजता का अधिकार का आधार
2. लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जरूरी
3. असन्तोष की अभिव्यक्ति
4. नवीन विचारों की खोज का तरीका
5. विविधता में एकता का आधार
6. हिंसा रोकने में जरूरी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निम्न सुधारों की आवश्यकता

① कार्यालय गोपनीयता अधिनियम 1923 में सुधार की जरूरत =

सैन्य जवाबदेही, आसूचना संस्थानों की वित्तीय जवाबदेही से रोकता है।

② टेलीग्राफ एक्ट 1885 में सुधार जरूरी ताकि फोन टैपींग रोका जा सके

③ संविधान अनुच्छेद 311 के तहत सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने में सुधार जरूरी।

④ अन्य सुधार- प्रशासकों को सार्वजनिक पुस्तक प्रकाशित करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्यांकन जरूरी।

अतः औपनिवेशिक कानूनों को वर्तमान जरूरतों अनुरूप मूल्यांकित करने की जरूरत संविधान समीक्षा आयोग 2000 ने भी बताई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Highlight the role of pressure groups in a democratic country. Also, differentiate between pressure groups in India and developed countries.

(150 words) 10

एक लोकतांत्रिक देश में दबाव समूहों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, भारत और विकसित देशों में दबाव समूहों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

दबाव समूह वे समूह होते है जो अपने हितो (सामूहिक) की पूर्ति के लिए संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक दबाव के तरीको का सहारा लेकर सरकार पर दबाव बनाते है।

दबाव समूह

- जातिय समूह
- CII, FICCI
- खाप समूह
- नक्सली समूह
- पर्यावरण समूह
- किसान समूह (AIKU)
- ST/SC समूह

भूमिका ① नीति निर्माण हेतु दबाव डालना ⇒ जैसे: लोकपाल कानून निर्माण हेतु अन्ना हजारे आंदोलन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② नीतियों - कानूनों को वापस लेने हेतु दबाव डालना ⇒

उदा: अखिल भारतीय किसान संगठन द्वारा कृषि कानून वापस लेने का दबाव

③ सुधारों की मांग = FICCI, CII

④ प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण की रक्षा करना।

अन्तर

भारत	विकसित देश
① अनौपचारिक अधिक	① औपचारिक अधिक
② सत्ता प्राप्ति की कोशिश नहीं	② सत्ता पर काबिज हो जाना - उदा. ब्रिटिश लेबर पार्टी
③ कम संगठित	③ अधिक संगठित
④ स्पष्ट नीतियों का अभाव	④ स्पष्ट नीतियों का अवलम्बन
⑤ हिंसक गतिविधियाँ	⑤ प्राय: कम हिंसक

इस प्रकार प्रशासन सुधार, जन अभिव्यक्ति में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. The idea that Public Intent Data can play a transformative role in the public sector is not bereft of challenges. Discuss. (150 words) 10

यह विचार कि लोक प्रयोजन डेटा (पब्लिक इंटेंट डेटा) सार्वजनिक क्षेत्रक में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है, चुनौतियों से रहित नहीं है। चर्चा कीजिए।

लोक प्रयोजन डेटा का तात्पर्य वह डेटा जिसको सार्वजनिक स्त्रोतो से एकत्रा किया जाता है तथा प्रशासनिक नीति निर्माण में प्रयोग होता है।

उदाहरण
1. आधार कार्ड डाटा
2. जैम (JAM) डाटा
3. राष्ट्रीय भूस्वामित्व डाटा
4. हेल्थ डाटा

परिवर्तनकारी भूमिका के रूप में

1. प्रभावी नीति निर्माण के रूप में बजट 2019 में लोक डाटा को 'भविष्य का ईंधन' माना गया।
2. औद्योगिक कार्यक्रम निर्माण में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महत्वपूर्ण - उदाहरण: बीमा क्षेत्र में

(3) लोगों की अभिरुचि समझने, और जरूरतों का पूर्वानुमान में सहायक जैसे - अमेजॉन डाटा

(4) स्टार्ट अप उद्यम, कृषि क्षेत्र, बाजार पूर्वानुमान, विकास अनुमान में सहायक। जैसे

(5) फेसबुक का मेटा डाटा के निर्माण में।

चिंताएं (1) निजता का उल्लंघन - पुट्टास्वामी वाद का उल्लंघन

(2) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण जैसे 90% डाटा गूगल के पास

(3) डाटा प्रबंधन में विशेषज्ञता का अभाव

(4) साइबर हमले, अवांछित डाटा संग्रहण

अतः AI, Big data विश्लेषण, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम जरूरी है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Enumerating the key objectives of the Foreign Contribution Regulation Act, discuss why the recent amendments in the act are seen as a matter of great concern for the development sector in India. **(150 words) 10**

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते हुए, चर्चा कीजिए कि इस अधिनियम में हाल के संशोधनों को भारत में विकास क्षेत्रक के लिए बड़ी चिंता का विषय क्यों माना जा रहा है।

विदेशी अभिदाय अधिनियम को सर्वप्रथम 1975 में लाया गया और 2010, 2012, 2015 तथा 2019 में संशोधन किया गया।

FCRA के उद्देश्य

① नियमों में स्पष्टता लाना ताकि विदेशी स्रोतों से अनुदान प्राप्त करने में समस्या न हो।

② विदेशी अनुदानदाताओं को प्रोत्साहित करना।

③ स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय क्षमता को बढ़ाना और NGOs में व्यापक सुधार लाना।

④ काले धन पर नियंत्रण करना

Call us : 8468022022, 9019066066 Visit us : www.visionias.in

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना।

हाल ही के संशोधन एवं चिंताएँ

① राजनीतिक दलों को चंदे से छूट के कारण राजनीतिक दलों के पास विदेशी चंदा आना संभव होगा यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है।

② कठोर नियमन के कारण केवल कुछ बैंक खातों में ही 'NGO' चंदा ले सकते है। यह मनोबल अधिक सख्ती करता है।

③ 'एन.जी.ओ' के लिए चंदा प्राप्ति कठिन हुई है।

अतः आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतं सहायक NGOs के मध्य संतुलन हो तथा राजनीतिक चंदे पर पुनः मूल्यांकन हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The current COVID-19 pandemic has posed a serious threat to the safety and wellbeing of children all over the world. Discuss. Also provide an account of the measures taken by the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) in this regard. (150 words) 10

वर्तमान कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में बच्चों की सुरक्षा और कुशलक्षेम के समक्ष एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा किए गए उपायों का विवरण भी प्रदान कीजिए।

यूनेस्को की हाल की रिपोर्ट अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों एवं उनके बचपन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

बच्चों पर प्रभाव

(1) बाल श्रम में वृद्धि - ILO की रिपोर्ट अनुसार करीब 1.2 करोड़ अतिरिक्त बाल श्रम कोविड कारण बढ़ा।

(2) घरेलू कार्यों में बालिकाओं का नियोजन बढ़ा।

(3) घरेलू हिंसा का प्रभाव बच्चों पर

(4) मानसिक तनाव, स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभाव देखा गया बच्चों पर।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) कोविड-19 का प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। दीर्घकाल में कोविड-संक्रमण के कारण बच्चों के फेफड़े ज्यादा कमजोर होंगे।

(6) शिक्षा, खेल से दूरी बनी है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किये उपाय

(1) घर-घर टीकाकरण उपलब्धता हेतु आशा कार्यकर्ताओं की मदद लेना।

(2) PDS तथा आंगनबाड़ी केंद्रों तक बच्चों की पहुँच बनाने की कोशिश।

(3) दूरदर्शन, रेडियो के माध्यम से नियमित कक्षाएँ जारी रखना।

(4) गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग, टैस्टिंग एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना।

अतः बाल सुरक्षा भावी राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Various challenges need to be addressed in order to successfully eradicate the menace of bonded labour in India. Discuss. (150 words) 10
भारत में बंधुआ श्रम के संकट को सफलतापूर्वक उन्मूलित करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

बंधुआ श्रम का तात्पर्य अमानवीय तरीके से ~~व्यक्ति~~ नागरिकों का श्रम में नियोजन होना है।

* संविधान के अनुच्छेद 23, 24 में बंधुआ श्रम के नियोजन सम्बंधित प्रावधान किया जाता है।

* 'वॉल्क फ्री फाउंडेशन' की रिपोर्ट अनुसार भारत में 1 करोड़ से अधिक बंधुआ श्रमिक विद्यमान है

बंधुआ श्रमिक का कारण

1. अशिक्षा, अज्ञानता
2. अधिकारों की जानकारी का अभाव
3. आर्थिक पिछड़ापन होना।
4. भूमिहीन श्रमिकों की अधिकता
5. कारगर/कारदकारी सुधारों का अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) प्रशासनिक उदासीनता एवं भ्रष्टाचार

(7) श्रम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाना।

(8) अनौपचारिक श्रमिकों की बहुलता

(9) परम्परागत श्रम ढाँचा।

अतः इन चुनौतियों का समाधान हेतु निम्न कदम उठाने की जरूरत है-

(1) बलात श्रम उन्मूलन कानून का कठोरता से पालन करना

(2) जुर्माना एवं सजा को और सख्त बनाना

(3) कृषि एवं आर्थिक सुधारों को गति देना

(4) श्रम संहिता कोड का क्रियान्वयन

(5) श्रम का औपचारिकरण करना

(6) अन्य सुधार - कौशल, शिक्षा

अतः मानव कल्याण और संविधान के पालन हेतु बलात श्रम समाप्त करना होगा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. In the background of the recent military coup in Myanmar, discuss why a stable Myanmar is important for India. (150 words) 10

म्यांमार में हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट की पृष्ठभूमि में, चर्चा कीजिए कि क्यों एक स्थिर म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

म्यांमार में हाल ही में सैन्य तख्तापलट हुआ और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार की जगह सेना ने प्रशासन अपने हाथो में ले लिया।

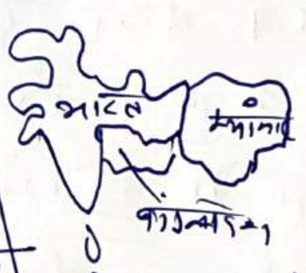

चित्र: म्यांमार

म्यांमार में तख्तापलट की यह तीसरी घटना है। जिसमें लोकतंत्र समर्थको को (सु की नेतृत्व) जेल में डाला गया।

स्थिर म्यांमार की भारत को जरूरत

(1) उत्तर-पूर्व राज्यों के विकास हेतु म्यांमार की स्थिरता, समृद्धि पूर्वशर्त है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

② 'एक्ट ईस्ट पोलिसी' तथा आसियान का प्रवेश द्वार म्यांमार से ही है।

③ भारत में सीमापार आतंकवादियों को रोकने तथा पूर्वोत्तर सीमापर शांति हेतु जरूरी।

④ भारत में ड्रग्स की सप्लाई (स्वर्णिम त्रिकोण) एवं हथियार आपूर्ति रोकने

⑤ रोहिंग्या शरणार्थी समस्या समाधान हेतु।

⑥ कालादान मल्टी मॉडल तथा गंगा मेकांग राजमार्ग निर्माण की सुरक्षा हेतु।

⑦ दक्षिण एशिया में अतिवाद रोकने के लिए

⑧ आर्थिक हितों की रक्षा हेतु गैस

अतः भारत को कूटनीतिक तरीके से म्यांमार की सेना को लोकतंत्र अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। आसियान की मध्यस्थता

10. In the case of Maldives it's not the size but the location that makes it strategically significant. Explain in the context of India's neighbourhood first approach. **(150 words) 10**

मालदीव के मामले में, आकार नहीं, बल्कि उसकी अवस्थिति उसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। भारत की 'पड़ोसी देश प्रथम' दृष्टिकोण के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।

मालदीव हिंद महासागर में भारत का पड़ोसी द्विपीय देश है। जिसका निर्माण प्रवाल द्वीपों पर हुआ है।

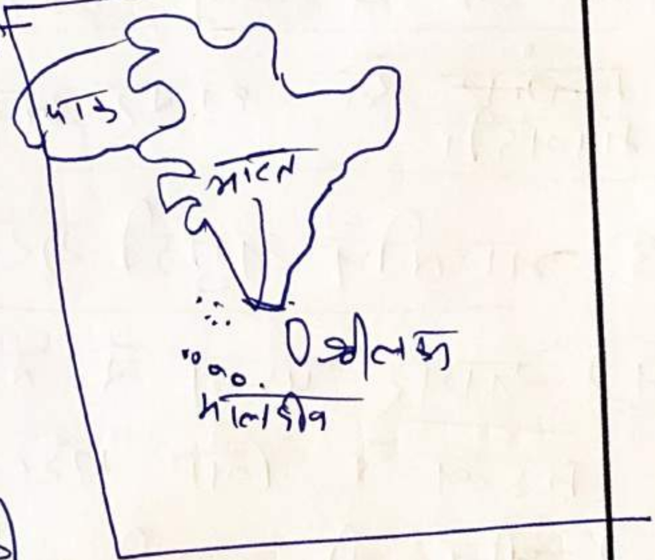

छोटे आकार के बाद भी मालदीव की अवस्थिति महत्वपूर्ण है –

① 'पड़ोसी प्रथम' की रणनीति के तहत भारत कूटनीतिक सहयोग और सहायता में पड़ोसी देशों की मदद करता है इसी कारण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत ने 2.5 बिलियन डॉलर की ऋण सहायता मालदीव को दी।

(2) मलक्का जलडमरू तथा फारस की खाड़ी का व्यापारिक मार्ग ~~[illegible]~~ मालदीव से होकर जाता है।

(3) भारतीय समुद्री सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण

(4) सागर पहल के तहत आर्थिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण

(5) चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने हेतु महत्वपूर्ण

(6) भारतीय पर्यटकों का प्रमुख गंतव्य

(7) 25000 भारतीय निवासी

(8) समुद्री डकैतों से सुरक्षा

(9) आपदा सुरक्षा, सैन्य निगरानी हेतु

अतः चरमपंथ रोकने, चीन को रोकने, तथा भारतीय व्यापार की सुरक्षा हेतु मालदीव महत्वपूर्ण है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. While the judiciary should not be a silent spectator when constitutional rights of citizens are infringed by executive policies, it must also not assume the role of the executive or pass policy prescriptions. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. **(250 words) 15**

जब कार्यकारी नीतियों द्वारा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो तब न्यायपालिका को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए, साथ ही इसे कार्यपालिका की भूमिका भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए अथवा नीतिगत निर्धारण जारी नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने रुख का औचित्य सिद्ध कीजिए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 में शक्ति पृथक्करण (कार्यपालिका - विधायिका - न्यायपालिका) का प्रावधान किया गया है।

किंतु संविधान समीक्षा आयोग 2000 ने न्यायपालिका से संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर हस्तक्षेप की अपेक्षा की है -

(1) संविधान के अनुच्छेद 13 और मूलाधिकारों की रक्षा में राज्य के नीतियों विरुद्ध न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है।

(2) संविधान अनुच्छेद 32 अपने

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आज में संविधान की आत्मा है (डॉ. अंबेडकर)
अतः मूलाधिकारों की रक्षा हेतु राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण।

(3) व्यापक लोकहित, तथा पब्लिक रुचि की याचिका (PIL) में जस्टिस भगवती ने 1980 में न्यायिक सक्रियता को जरूरी माना।

(4) जटिल होती लोक नीतियां और उनसे मूलाधिकारों में टकराव की स्थिति में हस्तक्षेप जरूरी
उदाहरण: ① पुट्टास्वामी वाद 2016 में निजता का अधिकार
② इंटरनेट का अधिकार (2020)

(5) जनता का सुशिक्षित होना, अच्छे शासन की बढ़ती मांग तथा न्यायिक विश्वास के कारण भी न्याय

न्यायपालिका हस्तक्षेप जरूरी।

न्यायपालिका की सीमाएं:

① विधि आयोग ने 3.5 करोड़ से अधिक लंबित न्यायिक वादों पर न्यायपालिका को ध्यान केंद्रित करने को कहा।

② न्यायपालिका कार्यकारी जटिलताओं को नहीं समझती है अतः हस्तक्षेप गैर जरूरी।

③ न्यायिक सुधार, पारदर्शिता की जरूरत एवं कार्यपालिका में मनोबल गिरता है।

अतः आवश्यक है कि शक्ति पृथक्करण की मूल भावना आधार पर ही निर्णय होना चाहिए और दोनों को अपनी मर्यादा अनुसार कार्य करना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. 'Effective legislatures are measured by their outcomes and not by their output.' Analyze the functioning of the Indian Parliament in this context.
(250 words) 15

'प्रभावी विधान-मंडलों का मापन उनके आउटकम्स (परिणामों) के आधार पर किया जाता है न कि उनके आउटपुट (निर्गत) के आधार पर।' इस संदर्भ में, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए।

भारतीय संसदीय विधानों की सफलता असफलता ही लोकतंत्र के रूप में मत संस्थानों के विश्वास को बताती है।

परिणामों के आधार पर विधानमंडलों का मापन =

① संसदीय सत्रों की संख्या के आधार पर संसद की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है।

② पारित विधेयकों की संख्या के आधार पर संसद की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परिणामों आधार पर मूल्यांकन में समस्या –

① संसदीय गतिरोध उत्पन्न होने को ~~सही~~ महत्व नहीं दिया जाता

② संसद में विधेयक पारित होने के तरीको में बहस, विचार, चर्चा सदस्यों को बोलने का समय, विपक्ष की आलोचना का ~~अधिकार~~ समय को सम्मिलित नहीं किया जाता।

③ सदन में हल्ला मचाना, विरोध प्रदर्शन, कार्यवाही में व्यवधान डालने को गुणवत्ता मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) नोट के बदले प्रश्न पूछने की घटनाएं
(5) अपने दल के खिलाफ वोट देने की स्वतंत्रता का अभाव होना।

वहीं निर्गत के आधार पर मूल्यांकन एक व्यापक संकल्पना है। इसमें कि -

(1) पंचायतों से आम लोगों की लोकतंत्र की समझ विकसित होने को महत्व दिया जाता है।

(2) लोक नीतियों की गुणवत्ता, आमसहमति, जन विश्वास को अपनाया जाता है।

(3) परिणाम आधारित दृष्टिकोण से अधिक व्यापक संकल्पना है।

हाल ही में ~~किसा~~ कृषि कानून, श्रम कानून पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कानून के आलोक में निर्गत आधारित मापदंडों का महत्व बढ़ गया है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Fiscal federalism in India has evolved with time. Discuss in light of the developments in recent years. (250 words) 15

भारत में राजकोषीय संघवाद समय के साथ विकसित हुआ है। हाल के वर्षों के घटनाक्रम के आलोक में चर्चा कीजिए।

राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य संघवाद के उस स्वरूप से है जिसमें वित्तीय स्रोतों का विभाजन संघवाद की भावना से होता है।

उदाहरण: ① केंद्र-राज्यों के प्राप्त वित्तीय अधिकार

राजकोषीय संघवाद का महत्व

① लोक कल्याण को सुनिश्चित करने में
② केंद्र राज्य विश्वास हेतु
③ लोकतंत्र का आधार।

समय के साथ राजकोषीय संघवाद का बदलाव

① 1947 के उपरांत शक्ति प्रबंधता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के तहत 7वी अनुसूची में केंद्र-राज्यों में शक्ति प्रबन्धन की गई

(2) संविधान अनुच्छेद 265, 267, 270 के तहत वित्तीय स्त्रोतों की स्पष्टता

(3) 1990s में 10वां वित्त आयोग की भावना अनुरूप सेवा कर का प्रार्दुभाव और राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्ति।

(4) वैल्यू एडीशन (Addition) टैक्स 2005 की शुरूआत हुई।

(5) जी-एस-टी प्रणाली द्वारा केंद्र-राज्यों द्वारा 17करों का एकीकरण

(6) 14वें वित्त आयोग द्वारा 42% राजस्व को राज्यों के साथ साझा करना

(7) 15वें वित्त आयोग ने 41% साझाकरण निर्धारित।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(8) योजना आयोग की समाप्ति उपरांत राज्य विशेष अनुदानों (275, 282) का तार्किकरण।

विनीय संघवाद में परिवर्तन के होने के कारण -

(1) कर प्रणाली का सरलीकरण 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' हेतु जरूरी

(2) नीति आयोग द्वारा 'नीचे से निर्माण' पर बल

(3) 73वां, 74वां संविधान संशोधन को अपनाना

(4) प्रत्यक्ष करों में सुधार की जरूरत

अतः इन्ही सब कारणों से राजकोषीय संघवाद में व्यापक परिवर्तन समय के साथ आता रहा है। पंचायतों, नगरपालिकाओं को अधिक वित्तीय समय की अभी जरूरत है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. The Central Bureau of Investigation (CBI) is often cited as an example of the rising politicisation of public institutions. In this context, identify the issues associated with the CBI's functioning. What steps can be taken to address these issues? **(250 words) 15**

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को प्राय: सार्वजनिक संस्थानों के बढ़ते राजनीतिकरण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। इस संदर्भ में, CBI की कार्यप्रणाली से संबद्ध मुद्दों की पहचान कीजिए। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत की प्रमुख अन्वेषण संस्था है। इसका गठन दिल्ली पुलिस विशेष अधि० 1945 के प्रावधानों के तहत किया गया है। यह प्रत्यक्षत: केंद्र सरकार के अधिकारिता और नियंत्रण (गृह मंत्रालय) में रहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 'CBI' को सरकार के नियंत्रण और राजनीतिकरण के कारण 'पिंजरे का तोता' कहा।

मुद्दे ① स्वायत्तता का अभाव

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

कार्मिक चयन हेतु राज्य पुलिस बलों पर निर्भर।

(2) अधिकार शक्तियां 'DPSPA' के तहत प्राप्त करने तथा स्वतंत्र विधायी अस्तित्व का अभाव।

(3) नियुक्तियों का राजनीतिकरण होना।

(4) आन्तरिक कार्यप्रणाली में असफलता CBI प्रमुख बनाम उपप्रमुख के मध्य टकराव।

(5) कार्यबल की कमी का होना।

(6) मामलों की जाँच राजनीतिक लाभ-हानि के रूप में करना और प्रायः विरोधी दलों को फंसाने का आरोप लगाना।

(7) भ्रष्टाचार और देरी के आरोप

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(8) पं. बंगाल, आंध्रप्रदेश द्वारा जांच स्वीकृति न देना।

उपाय जो उठाने वाले कदम

① <u>विधिक अस्तित्व</u> - संवैधानिक या <u>कैबिनेट</u> के माध्यम से होना चाहिए।

② <u>नियुक्ति</u>: गैर राजनीतिक एवं पर्याप्त जांच उपरांत निष्पक्षता आधारित हो।

③ <u>CVC</u> तथा <u>CBI</u> संबंधों में स्पष्टता और सुधार की जरूरत।

④ मामलों की जांच हेतु स्वायत्तता एवं कार्मिक प्रसार मिले।

⑤ राजनीतिक दबाव से मुक्ति मिले।

हाल ही में <u>CBI</u> सुधार की दिशा में प्रयास किये गये हैं आवश्यक है कि जनता का CBI में बना हुआ विश्वास बरकरार रहे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The principal constraint for India is trying to find solutions to 21st century problems using 19th century government structures. Discuss.

(250 words) 15

भारत के लिए प्रमुख बाधा 19वीं सदी के सरकारी ढांचे का उपयोग कर 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना है। चर्चा कीजिए।

19 वीं सदी में सरकारी ढांचा वर्तमान में 21वीं सदी की जरूरतों के लिए प्रयोग करने की आलोचना वी. सी होता समिति, वाई. के. अलघ समिति तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की।

19 वीं सदी का ढांचा जो वर्तमान में लागू है :—

① सिविल सेवा की उपस्थिति - 1782 में कार्नवालिस द्वारा की गई थी आज भी इसे प्रयोग किया जा रहा है।

② पुलिस को पुलिस अधिनियम 1861

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

के तहत प्रयोग लाना।

③ ब्रिटिश कानूनों की उपस्थिति-
- महामारी अधिनियम-1897
इस कारण कोविड-19 प्रबंधन में
चुनौतियां, अस्पष्टता आदि।

④ टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के
तहत राज्य द्वारा फोन टैपिंग एवं
निजता का उल्लंघन।

⑤ कार्यालय गुप्तबात अधिनियम 1923
वर्तमान में गैर जवाबदेही, भ्रष्टाचार
गैर संवेदनशील प्रशासन का कारण
है।

⑥ केंद्र-राज्य शक्ति वितरण वर्तमान
में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही,
शक्ति केंद्रीकरण का कारण बना
हुआ है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑦ अन्य ढांचे

न्यायप्रणाली वर्तमान परस्थितों अनुरूप नहीं - गैर पारदर्शिता, अंग्रेजी का प्रभुत्व, दिल्ली में केन्द्रीत, कानूनों की जटिलता पर आधारित है।

अतः आवश्यक है कि 'M.N वेंकटचेलैया समिति' की भावना और वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युक्त लोगों के अनुरूप सुधार हो।

आगे की राह - ① बेंक डोर प्रशासन में नियुक्तियां।
② डिजिटल ई-RTI, ई-कोर्ट
③ पुलिस सुधार प्रकाश सिंह वाद 2006
④ लोकपाल अधिनियम
⑤ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद
⑥ पुराने कानूनों की समाप्ति

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. How far has the governance in India achieved the twin objectives of transparency and accountability? **(250 words) 15**

भारत में अभिशासन (गवर्नेंस) ने पारदर्शिता और जवाबदेही के दोहरे उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है?

गवर्नेंस में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को अच्छे अभिशासन का प्रमुख आधार माना जाता है। (विश्व बैंक 1992)

नोलन समिति ने भी अच्छे प्रशासन हेतु पारदर्शिता और जवाबदेही को महत्व दिया।

पारदर्शिता

कार्यों की स्पष्टता, विधि का पालन, नियमों अनुरूप कार्य, लोगों के सामने प्रकटीकरण इसके घटक हैं।

पारदर्शिता के लाभ: जन विश्वास में वृद्धि होना, कानून का पालन होना, ईमानदारी की पुनर्स्थापना तथा भ्रष्टाचार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पर नियंत्रण होता है।

पारदर्शिता हेतु किये गये प्रयास

① सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्वतः प्रकटीकरण का प्रयास।

② ई-टेंडर, ऑनलाइन सेवा प्रदायगी द्वारा नियमों का स्पष्ट एवं सरलीकरण करना।

③ जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।

④ सिविल सेवा चार्टर की घोषणा द्वारा पारदर्शिता।

⑤ ई-FIR, ई-कोर्ट, ई-मित्र सिंगल विन्डो क्लीयरेंस को अपनाना।

जवाबदेही | कार्मों के प्रति वरिष्ठों एवं लोगों के लिए प्रति जवाबदेही होना |

प्रयास ① लोकपाल, लोकायुक्त
की नियुक्ति उदाहरण: बैंकिंग लोकपाल
② आंतरिक जवाबदेही - CVC, CAG की नियुक्ति द्वारा
③ सोशल ऑडिट

चिंताएँ
① सिविल सेवा चार्टर, सूचना अधिकार के तहत डाटा प्रबंधन का अभाव
② प्रशासनिक मनोवृत्ति छिपाने की |
③ अत्यधिक कार्यभार एवं मानसिक तनाव |
④ विवेकाधीन शक्तियों का अधिकता खासकर वरिष्ठों के स्तर पर
⑤ ब्रिटिशकालीन नियम प्रक्रियाऐं |
⑥ डिजिटल डिवाइड

अतः IInd ARC की सिफारिशों अनुरूप सुधार जरूरी है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Identify the barriers that exist in the enjoyment of reproductive health rights by women in India. Also highlight the interventions that have been adopted to remove these barriers. **(250 words) 15**

भारत में महिलाओं द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों का उपभोग करने के समक्ष विद्यमान बाधाओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इन बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए हस्तक्षेपों पर भी प्रकाश डालिए।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 के अनुसार बिहार, उत्तरप्रदेश में 75% महिलाये प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक तरीकों से दूर है।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा, गर्भवती माता के स्वास्थ्य की रक्षा, पोषण तथा गर्भधारण के अधिकार और सुरक्षित मातृत्व अधिकार से सम्बंधित है।

विद्यमान बाधाएँ

(1) स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता का 3000 की कमी है

(2) डॉक्टर : मरीज अनुपात का WHO के मानकों अनुरूप नहीं होना। 1:1456 अनुपात अत्यधिक डॉक्टरों की कमी को बताता है।

(3) प्रजनन को स्त्रीविरोधी दृष्टि से देखना कलंक, शर्म जैसे मुद्दों के कारण महिलायें प्रायः चर्चा नहीं करती।

(4) पर्दा प्रथा, पितृ सत्तात्मक समाज में पहले पुरुष भोजन करने जैसे प्रचलन महिलाओं में 'एनीमिया' के कारण

(5) शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव।

(6) 'LGBTQ' समुदाय के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव।

(7) वित्तीय आघात - सिजेरियन ऑपरेशनों का अवैध उपयोग के कारण।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

किये गये प्रयास

1. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 6000 रुपये की वित्तीय सहायता।
2. ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता का उपयोग कर गर्भनिरोधक दवा, एनीमिया दवा वितरण।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम 2013 के तहत विशेष प्रावधान ताकि गर्भधारण उपरांत पोषण हो सका हो।
4. 108 एम्बुलेंस सेवा
5. कोविड-19 में गर्भवती महिलाओं को विशेष छूट।
6. प्रचार-प्रसार द्वारा सुरक्षित गर्भ की जागरूकता।
7. साप्ताहिक 'माँ' पहल
8. मदर मिल्क बैंकों का निर्माण

अतः सभी प्रयास सही दिशा में है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. India continues to face the problem of hunger despite adequate food stocks and statutory laws that ensure food security. Discuss and provide solutions to deal with this problem. **(250 words) 15**

पर्याप्त खाद्य भंडार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वैधानिक कानूनों के बावजूद भारत भूख (हंगर) की समस्या का सतत सामना कर रहा है। चर्चा कीजिए एवं इस समस्या से निपटने के लिए समाधान प्रस्तुत कीजिए।

हाल ही में ग्लोबल हंगर इण्डेक्स अनुसार भारत को 102 वां स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक अनुसार 18.3 करोड़ भारतीय एक वक्त का भोजन ही कर पाते है।

किये गये प्रयास

① राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ करना।

② प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना।

③ मध्याह्न भोजन योजना।

④ आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) 'ff' जैसे फूड फोर्टिफिकेशन के प्रयास 'FSSAI' द्वारा

(6) टीकाकरण द्वारा टीको को सुनिश्चित करना।

(7) कालीक एसिड एवं विटामिन 'ए' की गोलियों का वितरण।

भुख की समस्या के कारण

(1) खाद्यान तक भौतिक पहुंच का अभाव - हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 करोड़ राशनकार्ड धारकों को आधार सक्षम नहीं होने के कारण खाद्यान नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त की।

(2) वित्तीय अक्षमता - विश्व बैंक अनुसार 1.9 डॉलर से कम कमाने वालो में भारतीय सर्वाधिक।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) गुणवत्ता युक्त पोषक तत्वों की उपलब्धता का अभाव - गेहूँ चावल पर ही अधिक निर्भरता।

(4) जागरूकता का अभाव - अशिक्षा

(5) फैशन - 'जीरो फिगर' का चलन

(6) माइक्रो न्यूट्रिशन का अभाव (कारण विटामीन, मिनरलों का अभाव)

(7) फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ना।

~~किन गमे~~ समाधान

(1) '+F' जैसे फोर्टिफाइड खाद्यान्नों को बढ़ावा देना चाहिए।

(2) खाद्यान्न तक ~~सार्वजनिक~~ सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।

(3) खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना ताकि खाद्य बर्बादी रोकी जा सके।

(4) लक्षित समूह पर ध्यान एवं वैज्ञानिक रणनीति अपनाना।

(5) जनजागरूकता अभियान चलाना।

19. The economic rise of Bangladesh is an opportunity for India and hope for South Asia. Examine. **(250 words) 15**

बांग्लादेश का आर्थिक उदय भारत के लिए एक अवसर और दक्षिण एशिया के लिए आशा है। स्पष्ट कीजिए।

बांग्लादेश ने हाल ही में प्रतिव्यक्ति आय के संदर्भ में भारत को पीछे छोड़ दिया। और दक्षिण एशिया में तीव्रतम आर्थिक विकास करने वाला देश बन गया है।

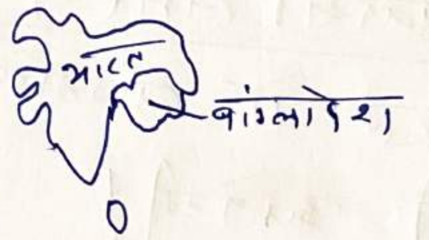

नक्शा: भारत-बांग्ला

इसी कारण से बांग्लादेश को आर्थिक उदय के संदर्भ में देखा जाने लगा है

आर्थिक उदय एक अवसर के रूप में

(1) भारत का कपड़ा उद्योग

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश पर निर्भर है। इस कारण यूरोप एवं अमेरिका में चीन का सामना करने की सफलता मिल रहे है।

② प्रवासी समस्या का समाधान
भारत में बांग्लादेशी प्रवास में कमी आयेगी।

③ भारतीय वस्तुओं का बांग्लादेश में अवैध निर्यात रूकेगा।

④ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाजारों को बढ़ावा मिलेगा।

⑤ विद्युत, सिमेंट, इस्पात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

⑥ सशक्त बांग्लादेश भारतीय उग्रवादी संगठनों को रोकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पश्चिम एशिया के लिए आशा

① नेपाल, भूटान के समस्त प्रतिभागियों आदर्श के रूप में स्थापित होगा।

② पाकिस्तान भी आतंक की जगह विकास को प्रेरित होगा।

③ चीन के ऋण जाल से देश बचेंगे।

④ SAARC 'FTA' को बढ़ावा मिलेगा

⑤ BBIN' परिवहन को गति मिलेगी

⑥ हिंद महासागर के देश आपसी व्यापार को 5% से आगे बढ़ायेंगे।

⑦ क्षेत्रीय समृद्धि यूरोपीय यूनियन की तरह आर्थिक यूनियन की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगी।

अतः भारत को बांग्लादेश की सहायता में अच्छे पड़ोसी की तरह सहायता करनी चाहिए।

20. Outcome of the Afghan peace process may have serious implications for the wider region. Discuss. (250 words) 15

अफगान शांति प्रक्रिया के परिणाम का अपेक्षाकृत व्यापक क्षेत्र के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं। चर्चा कीजिए।

हाल ही में अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के अपदस्थ होने और तालिबान के सत्ता में आने से दक्षिण-पश्चिम एशिया में अशांति को बढ़ावा मिला है।

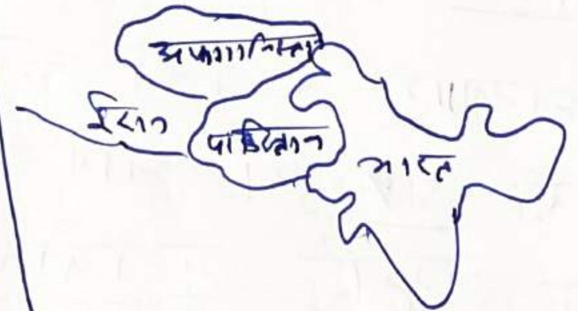

चित्र — अफगानिस्तान

अफगान शांति प्रक्रिया हेतु भारत, रूस, चीन, ईरान गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अफगान शांति हेतु तालिबान से 'कतर' में वार्ता कर रहा है

शांति वार्ता सफल होने के परिणाम

① क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता में वृद्धि होगी।

② लोकतंत्र और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

③ आतंकवाद पर नियंत्रण होगा।

④ मानवाधिकारों की रक्षा संभव

शांति वार्ता असफल होने के परिणाम

① तालिबान की सत्ता को वैधता मिल जाना

② महिलाओं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन होना।।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) भारत: 3 बिलियन से अधिक का निवेश खतरे में पड़ जाना।

(4) दक्षिण एशिया में ISIS तथा अन्य आतंकवादी समूहों का प्रसार होना।

(5) अफगानिस्तान का विघटन बढ़ना।

(6) अफीम तथा नशीले पदार्थों का व्यापार बढ़ना।

(7) सम्पूर्ण एशिया में चरमपंथी ताकतों का बढ़ना।

(8) लोकतंत्र के समक्ष चुनौती।

(9) पाकिस्तान में अतिवाद को बढ़ावा मिलेगा।

(10) चीन में शि-जियांग क्षेत्र में अतिवाद बढ़ेगा।

(11) मध्य एशिया में तनाव सैन्य खर्च बढ़ेगा।

अतः आवश्यक है कि तालिबान को स्थिर, लोकतांत्रिक, सशक्त अफगान की दिशा में प्रेरित करें।